



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124977

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5161 सन्
2026**

यामीन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद जी मिश्रा, कौशल कुमार पांडे, विशाल ओहरी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 74/2026 धाराओं 109(1), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(2), 125 और सीआर.एल.ए अधिनियम की धारा 7 पुलिस स्टेशन मुंडाली, जिला मेरठ में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए दी गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फँसाया गया है। आगे कहा गया है कि यह एफआईआर कूड़ा फेंकने को लेकर हुए झगड़े के कारण आवेदक समेत 15 नामजद लोगों और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक का उन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो उस पर लगाए गए हैं और उसने अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे कहा गया है कि घटना दो समूहों के बीच हुई बताई जाती है और आवेदक के खिलाफ कोई खास आरोप नहीं है; सभी आरोपियों की भूमिका सामान्य बताई गई है। आगे यह भी कहा कि घायलों को लगी चोटें मामूली हैं और किसी को भी गोली लगने जैसी चोट नहीं आई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे बताया गया कि तीन नामज़द आरोपियों - राशिद, आसिफ और अकील - को परीक्षण न्यायालय ने 10.4.2026 के आदेश से नियमित ज़मानत दे दी है और उनके ज़मानत आदेश की प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक संख्या 2 के रूप में लगाई गई है। आगे यह भी कहा कि हालांकि, इस मामले के अलावा आवेदक का 15 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उन्होंने आवेदक के पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है; इनमें से ज़्यादातर मामले 1990 से 1999 के बीच के हैं और दो मामले 2003 के हैं। अंत में कहा गया है कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से तय करते हुए कहा है कि अग्रिम ज़मानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित मामलों में, यह मुकदमे के खत्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि आरोपी के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी परीक्षण तक अग्रिम ज़मानत जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गवाहों को डराना-धमकाना की संभावना, और न्याय से भागने जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

6. अग्रिम ज़मानत से जुड़े स्थापित विधिक सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह प्रार्थना पत्र देने वाले को परीक्षण तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

8. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक-यामीन को इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर परीक्षण न्यायालय/विवेचना अधिकारी जैसा भी मामला हो, के सामने पेश होना होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानत देने पर परीक्षण खत्म होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर विवेचना अधिकारी/संबंधित न्यायालय के सामने पेश होगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, आवेदक को दी गई सुरक्षा रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

3 जून, 2026

के.के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।